

## भारत की डिजिटल क्रांति

## परिवर्तन का एक दशक और भावी योजना



राव इंद्रजीत सिंह

पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई है जो असाधारण है। जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों की एक शृंखला के रूप में शुरू हुई थीवह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग, और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जब संबद्ध मंत्रालयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों ने बड़े पैमाने में ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन को पूरा किया, तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्कैलेबल, नागरिक-प्रमुखतावाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है।

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएमएम) ट्रिपलटी की शुरुआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लगभग 55 करोड़

बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिचौलिया की सहायता से एक सिंगल मदरको कल्याणकारी लाभ सिधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है। यह वृद्ध वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रालय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैट कोसक्षम सहायता सेअमला कदम: एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्जी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स को जीवनरखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहाँ तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं।

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अक्सरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी पहलियां जनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया



है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढाँचा तैयार किया। डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने, और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया। डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरों के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज-रहित और संपर्क-रहित हवाई यात्रा को संभव बनाती है।

यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डों की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है। यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मात्र ऐप ही नहीं हैं - ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं। डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए, जेमने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है - जिसमें महिला उद्यमियों और एमएसएमई की बढ़ती संख्या शामिल है। राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संचिदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था। कृषि क्षेत्र, जिसे प्रायः परिवर्तन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है, ने भी डिजिटल साधनों को अपनाया शुरू कर दिया

है। पीएम-किसान जैसे प्लेटफॉर्म ने यह सुनिश्चित किया कि आय सहायता किसानों तक सीधे पहुँचे। ई-नैम ने राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सके। डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उन्हें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और अपनी भूमि में कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड के ग्रामीण-क्षेत्रों में, स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) उनके लिए एक प्रकार से डिजिटल जीवन रेखा बन गए, जो टेली-मेडिसिन से लेकर बैंकिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हर चीज की पेशकश करते हैं।

महामारी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के लिए एक कठिन परीक्षा थी जिसमें हम बखूबी सफल हुए। स्कूल बंद होने के बावजूद, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म ने यह सुनिश्चित किया कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे। लद्दाख और केरल के छात्र भी भारत भर के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपना आकार लिया, जिससे नागरिकों को एक डिजिटल आईडी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त हुई और अस्पतालों एवं राज्यों में एक सहज वातावरण बन सका।

वाणिज्य में भी एक शांत क्रांति देखी गई। डीपीआईआईटी की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अब छोटी किराना दुकानों

और हथकरघा बुनकरों को बड़ी ई-कामर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है। डिजिटल कॉमर्स के कार्यों को एकीकृत करके, ओएनडीसी प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय आसानी से लॉजिस्टिक्स, भुगतान और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों तक पहुंच सकें। नीति आयोग की अभिसरण भूमिका—मंत्रालयों, राज्यों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एकजुट करना है—जो सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं अंतर-संचालनीय, समावेशी और स्केलेबल हों। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैं—ईआई—सक्षम शासन, विकेंद्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएं जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं।

लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी सफलता से जुड़ी कहानी नहीं है। यह एक राष्ट्र की कहानी है—करोड़ों नागरिकों की कहानी है जिन्होंने बदलाव को अपनाया, उद्यमियों की कहानी है जो डिजिटल रेल पर आगे बढ़े, और स्थानीय लीडरों की कहानी है जिन्होंने सेवा वितरण की नई कल्पना की। भारत का डिजिटल दशक सिर्फ तकनीक का नहीं है—यह बदलाव का दशक भी है और यह कहानी का अभी प्रारंभिक चरण ही है।

(लेखक साहित्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।)

## व्यंग्य

## नेताओं के मुंह से झर रहीं गालियां... आओ बजाएं सब तालियां...!

रवि उपाध्याय  
लेखक व्यंग्यकार और राजनीतिक समीक्षक हैं।

मित्रों, यह हम सब बखूबी जानते हैं कि गालियां हमारी चिकित्सीय परीक्षा हैं। गालियों की संवर्धन उपति छत्र और कहां हुई यह तो ठीक ठीक से नहीं बताया जा सकता लेकिन एक बात दावे से कही जा सकती है कि जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया होगा वैसे वैसे गालियों का भी विकास होता गया होगा। बाद में धीरे धीरे यह एक लोकभाषा के रूप में विकसित हो गई। आज हालात यह हैं कि नेताओं द्वारा बयान और भाषणों में गालियों का उपयोग अलंकार या मुहावरों के तौर पर किया जाता है। इन दिनों नेताओं द्वारा इनका उपयोग स्वयं को निडर बताने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी किया जाने लगा है। यह सभी मर्यादाओं और भाषाई तटबंधों को तोड़ने का साधन बना दी गई हैं। गालियों को साहित्यिक भाषा में दर्जित कहा जा सकता है। यह शब्द कितना साहित्यिक और सुसंस्कृत लगता है। यह शब्द गुस्सेल ऋषि दुर्वास मूनि का भी आभास कराता है।

इस विधा की लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पहले इस लोक संवाद का उपयोग मन ही मन किया जाता था। परंतु जैसे जैसे हमारी सभ्यता जवान होती गई। ये बुदबुदाहट, बाद में लाउड हो कर लाउडस्पीकर तक जा पहुंची। जैसे-जैसे सभ्यता जवान की सीढ़ियां चढ़ती गईं। नेताओं के संपर्क से यह गालियां सार्वजनिक सभाओं और मंचों की मुख्य विषय वस्तु बन गईं। इसे लोकप्रिय बनाने में नेताओं का यह प्रयास भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णशरीरों में लिखा जाएगा। वैसे हम सब यह भलीभांति हैं जहां काम सुंदर से चल सकता हो वहां तलवार को मियान में ही पड़े रहने देना चाहिए। संत कवि रहीम चचा ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि जहाँ काम आवे सुई, वहाँ करे तख्तार। आज तक तलवार का उपयोग कौन करता है? इसके अंशत तो तुरंत के दौरान एक ही विशेष तबके के द्वारा किया जाता रहा है। आज कल तलवार पुराना चलन की बात हो गई है। अब तो तमंचों और गालियों, पेट्रोल बमों, गुलेलों का चलन है। यह सब तो हिंसा के हथियार हैं। लेकिन गालियां देना पूर्णतः अहिंसक प्रक्रिया है। इनका प्रयोग होते ही अगले बंदे के प्राण सुख जाते हैं और वह सरेंडर कर देता है। महिलाओं का एक ऐसा हथियार है जिससे दरो दिवार कांज जाते हैं और वह हथियार है गगन भेदी अट्टहास, महिलाओं की चौधरी इसका उपयोग देश के सबसे बड़े पंचायत भवन में कर चुकी हैं। उनकी अट्टहास से पंचायत भवन की छत और दीवारों से प्लस्टर तक जमीन पर आ गिरा था। वह तो शुक मनाओं की उस भवन का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। वरना आज के जमाने वो बना होता तो वह उसी समय सभी पंचों को लेकर जमींदार हो गया होता।

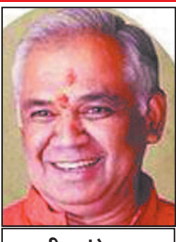
आजकल के नेताओं के शौक भी अजीब होते हैं। नेता बिना किसी शर्मों हया के दिनदहाड़े एक दूजे को आंख मारने में, पुरुष को आलिंगन करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। परंतु बता दें कि इस तरह की हरकत करने वालों को 'गे' कहा जाता है। अब बात गालियों के अस्तर की तो, गालियों का अस्तर वैसा ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अहिंसा की अहिंसा और हिंसा की हिंसा। इसे सुनते ही कमजोर इंसान तो तुरंत, तुम ही हो माता, तुम ही हो श्लोक पढ़ने लग जाता है। गाली देना चाणक्य नीति के समान है। बिना खुन खराबा किए फतह पाने जैसा है। गालियों की गर्जना चुनकर आस पास के श्रोता गुण लंबे समय तक खुद ब खुद आपको दर्शन भाना बैठते हैं। आप और हम भला तो क्या खाल गालियां देंगे। इस मामले में निम्न मध्यम वर्ग की स्त्री-पुरुषों का गालियों का कोष अत्यंत समृद्ध है। झुग्गी बस्तियों में जब दो महिला दलों के बीच जब गालियों का मुकाबला होता है, अहा! मजा ही आ जाता है। उस समय दोनों टीमों में क्या जोश और जज्बा होता है वह दांतों तले उंगली दबाने वाला होता है। गालियों का अस्तर सैकड़ों राउंड गाली चलाने से गहन गंभीर होता है। इसका एक लाभ यह भी है कि इन्हें बच्चे बड़ी तेजी से केवल सीख ही नहीं जाते अगले कुछ देर में अपने संगी साथियों पर धड़ धड़ उपयोग भी कर डालते हैं। गालियां व्यक्त की आक्रोश, कुट्टा और बीपी को कम करने का मुख्य साधन बन गई हैं। ये शोषक द्वारा शोषित के प्रति और मालिक का दास के प्रति साधिकांर किया जाने वाला स्वस्ति वाचन बन गया है। विधि की पुस्तकों में बताया गया है कि किसी को भी गाली देना कानूनन अपराध है। पर कुछ थोड़ा लोंग जो कानून को अपनी जेब में रख कर उसे भी गालियों से सुशोभित करने से परहेज नहीं करते हैं। आधुनिक समय में गाली को जिस तरह उपयोग किया जाता है वह गैर कानूनी बन गया है। जहाँ तक हमारी पुरातन परंपरा की बात है तो हमारी संस्कृति में गालियों को मीठी, छेड़छाड़ की एक लोक विधा के रूप में उपयोग किया जाता है। आज भी ग्रामीण अंचलों की शादियों में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले विवाह गीतों और गायन में समधी और समधनो के लिए लोकगीतों में गालियों का उपयोग किया जाता है। वह एक हंसी टिटोली और मजाक में ली जाती है। इस पर न तो वह पक्ष बुरा मानते हैं और न ही वधू पक्ष और न ही बारात में आए बाराती ही इसका बुरा मानते हैं। बल्कि इसी के उलट दोनों पक्ष इसका मजा लेते हैं। कभी कभी तो वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा लोकगीतों के माध्यम से दी गई गालियों का जबाब, बारात के संग आई दर पक्ष की महिलाओं द्वारा गालियों का उसी तरह गीतों में जवाब दिया जाता है। इसी तरह होली पर गाए जाने वाले फ्राग गीतों में भी लोकभाषा में गालियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के गीत उत्तरप्रदेश और बिहार में खूब गाए जाते हैं। जहाँ तक समाज में गालियों की स्थिति की बात की जाए तो इसके दो पक्ष हैं। एक ओर तो यह दोस्ती में प्रगाढ़ता का प्रतीक है वहीं यह नफरत के स्तर को भी प्रदर्शित करती है। जिगरी दोस्ती के बीच जो गालियों का आदान प्रदान होता है वह एक मीठी नोकझोंक होती है।

डा. अजय शर्मा  
(लेखक साहित्यकार हैं।)

राज भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। हर बार हम लोग हिंदी दिवस मना कर सरकार से मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बना दिया जाए। हर राज्य की अपनी एक मां बोली है, यानी खूबसूरत भाषा है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के हर प्रांत की मातृ भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है। जिस दौर से हम लोग गुंजर रहे हैं, वह ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस दौर में तरक्की वही इंसान कर सकता है, जो मल्टी लिंगल होगा। उसका सीधा कारण है, जहां मातृ भाषा हमें संस्कार और संस्कृति से जोड़ती है, वहीं राज भाषा हिंदी भाषा हमें हर प्रांत से जोड़ने का कार्य करती है।

2006 में मैंने उपन्यास शहर पर लगी आंखें लिखा था और उसमें यह स्थापित की थी, जितनी भाषाएँ किसी इंसान की गुंजर होती हैं, उतने ही व्यक्ति उसके अंदर होते हैं। इसके बावजूद, भारतवासियों को एक ऐसी भाषा की जरूरत है, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। अगर हम उस भाषा की बात करें, तो वह हिंदी के अलावा कोई नहीं हो सकती। इसलिए यह बात बहुत जरूरी है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए। आज तीन चौथाई आबादी हिंदी बोल लेती है, पढ़ लेती है। 1949 में राज भाषा घोषित किया गया था और 1953 में पूरे देश में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। हिंदी भाषा इतनी तरल और सरल है, जिसे हर कोई व्यक्ति आसानी से

## उपराष्ट्रपति चुनाव!

राजीव खंडेलवाल  
(लेखक वरिष्ठ वर सलाहकार एवं पूर्व चुनाव न्याय अय्यक हैं।)

इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी- सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 152 मतों के अंतर से जीत मिली। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया। जिनमें से 752 वोट वैध और 15 वोट अवैध घोषित हुए। ये आंकड़े आशाओं से अधिक होकर आशंकाओं को लगभग निर्मूल करते हैं। तथापि ये आंकड़े ऊपर से जितने सामान्य दिखते हैं और जो सामान्य परिणाम को दर्शाते हैं। वास्तव में स्थिति वैसी है नहीं। यदि इन आंकड़ों की गहन चीर-फाड़ की जाए, तो उसमें छुपे उसके कई अर्थ और अनर्थ भी निकलते हैं।

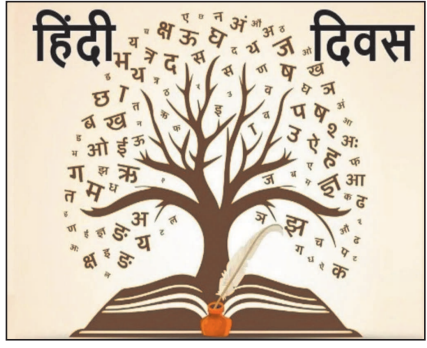
असंभव को संभव कर दिखाया - एक म्यान में दो तलवारों (परस्पर दुश्मनों की) साथ कैसे रह सकती हैं? इस असंभव को संभव करने का कोई करिश्मा किसी ने दिखाया है। तो ये शक्य हैं। देश के राजनैतिक नेतृत्व के प्रधानमंत्री के बाद नंबर दो कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह। जिन्हें समय-समय पर चाणक्य, लौह पुरुष आदि संज्ञाओं से नवाजा भी जाता है। उक्त चुनाव परिणाम अमित शाह के इस नेतृत्व को सिद्ध करता है। -आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दोनों को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए साथ खड़ा कर लेना सामान्य रणनीति नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत समर्थन के साथ अमित शाह की यही राजनीतिक चतुराई चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित हुई। उल्लेखनीय यह भी है कि जगन रेड्डी यदि चाहते] तो नायडू से दूरी दिखाने के लिए बीजेडी, टीआरएस, शिरोमणि अकाली दल की तरह मतदान से अनुपस्थित रह सकते थे] किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं।

सिर्फ देश के प्राइड राधाकृष्णन - इस चुनाव में एक ओर

## हिंदी दिवस पर विशेष

समझ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बालीवुड में हिंदी की फिल्मों में लगती हैं और देखी जाती हैं। आज हिंदी के अखबार किसी भी दूसरी भाषा के अखबारों से सबसे ज्यादा छपते हैं। इसका सीधा अर्थ है, हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़ा हुआ है।

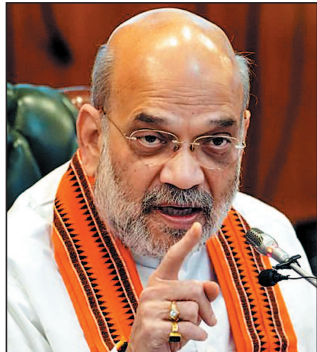
हिंदी में वह शक्ति है, जो सभी प्रांतों के लोगों को



संपर्क भाषा के रूप में अपने जोड़ सकती है। आज सोचता हूँ तो यह भी लगता है, जब हिंदी को राज भाषा बनाया गया, तब हर प्रांत की भाषा को राष्ट्र भाषा कर देना चाहिए था। कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आरंभ कभी प्रचंड नहीं बन सका। जिस दिन आरंभ प्रचंड बन जाएगा, उस दिन विचारों की क्रांति आएगी और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बड़ी आसानी से स्वीकार

## अमित शाह अमित छाप छोड़ गए

## न तेलुगू प्राइड! न तमिल प्राइड! सिर्फ देश का प्राइड



राज्यीय पहचान से ऊपर है। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड्गे—दोनों को इसका श्रेय जाता है। वैसे राज्य की अस्मिता से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का झंडा लेकर चलने वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड्गे को आगे आकर राज्य की अस्मिता से ऊपर देश के अस्मिता रखने के लिए बधाई जरूर देनी चाहिए।

भारी विजय! लेकिन ऐतिहासिक नहीं- राधाकृष्णन को 152 वोटों से जीत भारी है। क्योंकि उन्हें अपेक्षा से अधिक मत मिले। लेकिन यदि तुलना वर्ष 2022 से करें, तब जगदीप धनखड़ ने मांगरिट अल्ला को 528 बनाम 182 यानी 346 वोटों के भारी अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस दृष्टि से राधाकृष्णन को जीत भारी तो कही जा सकती है। पर ऐतिहासिक कदापि नहीं। दोनों उम्मीदवारों को अधिकृत वोट क्रमशः 438 एवं 315 वोट थे। 28 अतिरिक्त वोटों में से 14-14 दोनों उम्मीदवारों को मिले। तीन क्षेत्रिय पार्टियों व एक निर्दलीय चुनाव में अनुपस्थित रहे।

क्या अवैध मत डालने वाले ये 15 सांसद अनुपयुक्त नहीं- देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए और संविधान लागू हुए 75 वर्ष। फिर भी

## कई प्रदेशों में हिंदी साहित्य अकादमी नहीं

आवाज उठाई, वह हिंदी थी। विभिन्न प्रांतों के बावजूद, हिंदुस्तानियों ने कोई भाषा चुनी तो वह हिंदी थी। उस समय हमी हिंदी ने संपर्क भाषा का काम किया और जन-जन की भाषा बन।

देश की जनता जानती थी, देश के हर कोने में हिंदी हर कोई समझता है। अगर समूह को इस आंदोलन में जुड़ सकता है, तो वह केवल हिंदी से जुड़ सकता है। भारत आजादी का महोत्सव मनाने में मसरूफ है। जाहिर सी बात है, भारत को आजाद हुए साढ़े सात दशक से ऊपर हो चुके हैं। अगर मैं मैं हिंदी

प्रदेशों की बात करूँ, तो हिंदी को जिंदा रखने में हर प्रांत का अहम योगदान है। भारतीय भाषाओं में हिंदी का वही स्थान है, जो नदियों में गंगा का। गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, तो एक छोटी-सी धारा के रूप में दिखाई देती है। लेकिन जैसे-जैसे नीचे आती जाती है, वह अपना विशाल रूप धारण करती जाती है। हिंदी की पहचान भले ही राष्ट्र भाषा के रूप में न बन पाई हो, लेकिन लिंक भाषा या राज भाषा के रूप में अपनी दस्तक देती रहती है। गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो भाई चारे की बात भी होती है। ऐसे ही हिंदी में छपा हुआ लेख, चाहे वह किसी भी भाषा में लिखा गया हो, वह क्षेत्रिय सीमा को पार कर जाता है और व्यापक रूप धारण कर लेता है। अगर मैं कहूँ कि भारतीय भाषाओं में हिन्दी का वही स्थान है, जो नदियों में गंगा का है, तो गलत न होगा।

आज भी हिंदी की स्थिति के बारे में बात करूँ, तो हिंदी देश की हदें सरहदें तोड़ कर बाहर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी के कुछ शब्द तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी दर्ज कर लिए हैं। ऐसा माना जाता है जब पंजाब का हिंदी भाषा को समूह करने में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बदकिस्मती यह है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी पंजाब समेत कई प्रदेशों में हिंदी साहित्य अकादमी नहीं है। उसकी कमी हमेशा खटकती है और खटकती रहेगी। सरकारों को चाहिए फिर हर प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना की जाए, ताकि हिंदी का प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक किया जा सके और हिंदी जन-जन तक पहुंच कर सशक्त रूप से संपर्क भाषा बन सके।